



भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड

प्रिलमिस के लिये:

भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड, पूंजी बाज़ार।

मेन्स के लिये:

वैधानिक निकाय, अर्द्ध-न्यायिक निकाय, पूंजी बाज़ार, सेबी के साथ मुद्दे और आगे का रास्ता।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड (SEBI)** की पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवी पुरी बुच को इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वह तीन वर्ष तक इस पद पर बनी रहेंगी।

- इससे पहले जनवरी 2022 में सेबी ने **Saarathi** - नविशक शिक्षा पर एक मोबाइल एप लॉन्च किया था।

भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड (SEBI)

परिचय:

- सेबी भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय (एक गैर-संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया) है।
- सेबी का मूल कार्य प्रतभूतियों में नविशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतभूत बाज़ार को बढ़ावा देना एवं वनिमियमि करना है।
- सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं।

भूमिका:

- सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक (Controller of Capital Issues) नियामक प्राधिकरण था; इसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे।
- अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाज़ार के नियामक के रूप में किया गया था।
- प्रारंभ में सेबी एक गैर-वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी।
- सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना तथा इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।

सेबी की संरचना:

- सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा कई अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- यह समय-समय पर तत्कालीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों की जाँच हेतु विभिन्न समितियाँ भी नियुक्त करता है।
- इसके अलावा सेबी के नरिणय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिये एक **प्रतभूत अपीलीय न्यायाधिकरण-सैट (Securities Appellate Tribunal- SAT)** का गठन भी किया गया है।
 - SAT में एक पीठासीन अधिकारी तथा दो अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
 - सेबी के पास वही शक्तियाँ हैं, जो एक दीवानी न्यायालय में नहिति होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 'प्रतभूत अपीलीय न्यायाधिकरण' (SAT) के नरिणय या आदेश से सहमत नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

सेबी की शक्तियाँ एवं कार्य:

- सेबी एक अर्द्ध-वधायी और अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो वनिमियों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है तथा जुर्माना लगा सकता है।
- यह तीन श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्य करता है-

- **जारीकर्त्ता-** एक बाज़ार उपलब्ध कराना जिसमें जारीकर्त्ता अपना वित्त बढ़ा सकते हैं।
- **नविशक-** सही और सटीक जानकारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करके।
- **मध्यवर्ती/बचौलथि-** बचौलथियों के लिये एक प्रतस्पर्द्धी पेशेवर बाज़ार को सक्रम करके।
- प्रतभूता कानून (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा सेबी अब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशा की कसी भी मनी पुलगि योजना को वनियमि करने तथा गैर-अनुपालन के मामलों में संपत्त को संलग्न करने में सक्रम है।
- सेबी के अध्यक्ष के पास "तलाशी/जाँच और ज़बती संबंधी ऑपरेशन" का आदेश देने का अधिकार है। सेबी बोर्ड कसी भी प्रकार के प्रतभूत लेन-देन के संबंध में वयक्तया संस्थाओं से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है।
- सेबी उद्यम पूंजी कोषों और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक नविश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण तथा वनियमन का कार्य करता है।
- यह स्व-नियामक संगठनों को बढ़ावा देने उन्हें वनियमि करने और प्रतभूत बाज़ारों से संबंधित धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतबिधित करने के लिये भी कार्य करता है।



मुद्दे और संबंधित चिंताएँ

- हाल के वर्षों में सेबी की भूमिका और अधिक जटिल हो गई है।
- बाज़ार के आचरण के नयिमन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि वविकपूरण नयिमन पर कम।
- सेबी की वैधानिक प्रवर्तन शक्तियाँ अमेरिका और ब्रिटन में इसके समकक्षों की तुलना में अधिक हैं क्योंकि गंभीर आर्थिक कषत के लिये दंड देने के मामले में यह तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तशाली है।
- यह आर्थिक गतिविधि पर गंभीर प्रतबिध लगा सकता है, ऐसा नवारिक नरीध कसी तरह के संदेह के आधार पर किया जाता है।
- अधीनस्थ कानून बनाने के लिये सेबी अधिनियम के व्यापक वविकाधिकार के रूप में इसकी **वधायी शक्तियाँ नरिपेक्ष** हैं।
- बाज़ार के साथ पूरव परामर्श का घटक और वनियमों की समीक्षा की एक प्रणाली (जो यह देखने के लिये तैयार की गई है कि क्या वनियम वयक्त किये गए उदेश्यों को पूरा करते हैं) काफी हद तक अनुपस्थिति है। परणामस्वरूप नयिमक की शंका व्यापक है।
- वनियमन, चाहे वे नयिम हों या प्रवर्तन, वशिष रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे कषेत्रों में परणुरणता से बहुत दूर है।
- प्रतभूतियों की पेशकश करने वाले दस्तावेज़ असाधारण रूप से वज़न में भारी होते हैं और उनके औपचारिक अनुपालन हेतु उनकी उच्च गुणवत्ता के वास्तविक प्रकटीकरण के बजाय संख्या को काफी हद तक कम कर दिया गया है।

आगे की राह

- वास्तव में एक अभवित्तिक प्रवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि बाज़ार के बारे में सैकड़ों की संख्या में ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जो दर्शाती हैं कि बाज़ार अपराधियों से भरा हुआ है जिसके चलते सख्त कार्रवाई और गंभीर हस्तकषेप करने की आवश्यकता है।
- बाज़ार को और बेहतर कैसे बनाया जाए इस संदर्भ में सेबी को गहन समीक्षा और शोध करने की आवश्यकता है। फंड्स के आकार में वृद्धि कभी भी सफलता का मानक नहीं हो सकती और न ही यह प्रदर्शाति कर सकती है कि बाज़ार वनियमन के इस खंड/कषेत्र में कैसा प्रदर्शन हो रहा है।
- सेबी को अपने संगठन के अंतर्गत मानव संसाधन और इससे संबंधित मामलों पर वशिष ध्यान देना चाहिये।
- वायदा बाज़ार आयोग के सेबी में वलिय के बाद वरषिठ कर्मचारियों का संरेखण और नयुक्ति का कार्य का एक खुला कषेत्र बना हुआ है।
- नरितर नगिरानी और बाज़ार की खुफिया जानकारी में सुधार के साथ प्रवर्तन को मज़बूत किया जा सकता है।
- भारत के वत्तीय बाज़ार एक-दूसरे से वभिजाति हैं। वत्तीय उत्पादों की ओवरलैपिंग के मामले में एक नयिमक को दूसरे की वफिलता के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
 - इस संदर्भ में एक एकीकृत वत्तीय नयिमक, ओवरलैप तथा अपवर्जति सीमाओं दोनों के वषिय में उत्पन्न गतरिध को दूर करने का प्रयास कर सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/securities-and-exchange-board-of-india-1>

